Publication: Business Standard **Date: Monday, 21st September, 2015**

Edition: Delhi

आपका पक्ष

मानवीय मूल्यों से प्याज का समाधान

प्याज बहुसंख्यक जनसंख्या के भोजन का प्रमुख आधार है। यह रुचिकर, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ-साथ सब्जियों में सर्व सुलभ और सस्ता माना जाता है। इससे देश की आम जनता अपने भोजन की व्यवस्था सहजता के साथ कर लेती है। कई वर्षों से अचानक बेमौसम प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। प्याज की कीमतें बढ़ने से सरकार हिलने लगती है। विपक्ष और स्वयंसेवी संस्थाएं इस मामले में हाय तौबा मचाने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन इस दिशा में आज तक कोई समाधान खोजने की कोशिश नहीं की गई है। आखिर चंद दिनों में प्याज कहां और कैसे गायब हो जाता है, इसके पीछे कोई न कोई चाल या साजिश जरूर होती है। आज स्थिति यह हो गई है कि सब जानते समझते हुए भी जनता मौन है क्योंकि वह जानती है कि अभाव पैदा करके उसे ठगा जा

रहा है। आखिर उत्पादन हो रहा है तो प्याज कहां जा रहा है। अगर देश से इसका निर्यात किया जा रहा है तो क्यों जबकि देश में प्याज का अभाव होने के कारण इसके दाम आसमान छू रहे हैं। आज भौतिकवादी युग में पैसा प्रधान हो गया है। नैतिकता आदर्शवादिता एवं समाज सेवा सिर्फ दिखावे की चीज बन गई

पिछले दिनों देश के कई राज्यों में प्याज के दाम करीब 80 रुपये तक पहुंच गए थे

है। आज सवाल सिर्फ प्याज का नहीं है बल्कि हमारे समाज में अनेक ऐसी बीमारियां हैं कि हम अर्थ लालसा में लिप्त होते जा रहे हैं। इस व्यापार से जुड़े व्यक्ति की सत्ता महत्ता व्यापकता को स्वीकार करके मानवीय मूल्यों के प्रति सजग होकर नैतिकता के साथ उदार भाव रखे तो प्याज की कीमतों का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा। इसकी कीमतों पर लगाम कसी जा सकेगी। इसके लिए सरकारी पहल के साथ ही लोगों को स्वयं ही पहल करनी होगी।

डॉ अशोक कुमार, कानपुर

एलआईसी की डिजिटल पॉलिसी

अब भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) डिजिटल पॉलिसी जारी करेगा। पॉलिसी क्षेत्र में अब तक का यह सबसे बड़ा कदम है। डिजिटल इंडिया की आवाज आज विश्व पटल पर गूंज रही है। ऐसे में एलआईसी द्वारा उठाया गया यह महत्त्वपूर्ण कदम सराहनीय है। इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस ने सितंबर 2013 में पहला डिजिटल पॉलिसी पेश की थी। हालांकि अभी भी भारत में दो फीसदी से भी कम पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बिकती हैं। अब एलआईसी के ई-बीमा प्रक्रिया बन जाने के बाद चीजों में बदलाव आ सकता है। एक ओर जहां बीमा पॉलिसियों को बीमा रिपॉजिटरी के जरिये डिजिटल रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा वहीं बीमा रिपॉजिटरी (आईआर) एक बीमाधारक को बीमा पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और उसे अपने से सहेजने में मदद करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये रिपॉजिटरी, शेयर डिपॉजिटरी या म्युचुअल फंड एजेंसी की तरह लोगों को जारी की गई बीमा पॉलिसियों का रिकॉर्ड रखेगी। इन पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी या ई-पॉलिसी का नाम दिया गया है जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाते में रखा जा सकता है।

अशोक कुमार, दरभंगा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

A Joint Venture of Bank of Baroda Legal & General Andhra Bank